(a) whether the production of natural rubber in the country will be able to meet the entire demand in the near future; and

(b) if not, whether Government propose to fill the gap between supply and demand by increased production of synthetic rubber and by resort to new plantation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). The production of natural rubber in the next two years will meet the demand of the rubber manufacturing industry. However, such demand is likely to go up when the additional licensed units go into production. Production of synthetic rubber in the proposed public sector unit will adequately cover the Fourth Plan demand for rubber.

कोटा, उदयपुर सबसेर और जयपुर रेलवे स्टेझनों पर डूटे हुए माल डिब्बो की नीलामी के समय उपस्थित ' पार्टियां

7064. भी लाल जी माई : भी सोंकार लाल बेरवा:

क्या रेलवे मंत्री यह वताने की क्रुपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कोटा उदयपुर ग्रजमेर और जयपुर रेलवे स्टेननों पर हुई नीलामी में किन-किन पार्टियों ने टूटे हुए माल डिब्बे बरीवे; और

(स) मास विम्बों की नीलामी से कितनी बाय हुई ?

रेख संजी (की के हनुमन्द्रेया): (क) एक सुवी सभा पटक पर रक्षी है। [ग्रन्थालय]में रखा गवादेखिये शंख्या ८ -3028-72]

(ब) कोटा	10,98,431 रुपये
उदम्पुर अपमेर	कुछ नहीं। 18,18, 220 रुपये
4494	कुछ नहीं। 29,16, 651 खर्च

उदयपुर, कोटा और व्ययपुर के रेसवे अस्पतालों में दवाइयों का स्टाक

Written Answers

7065. भी लालजी भाईं: क्या रेल मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर, कोटा और जयपुर स्थित रेलवे अस्पतालों में दबाइयों का समुखित स्टाक नहीं रहता है जिसके परिणाम स्वरूप तृनीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हो, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (भी के हनुमन्तैया): (क) उदयपुर, कोटा ग्रीर जयपुर के रेलवे ग्रस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं है। यदि देरी से सप्लाई किये जाने के कारण किसी खास दवा की कमी पड़ जाती है तो डाक्टर अपने भांध-कारों के ग्रन्तगंत इस दवा को स्थानीय बाजार से खरीद लेते हैं।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय को विलासपुर से उड़ीसा से जाना

7066. भी चन्तूलाल चन्द्राकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंने किः

(क) उनका मंत्रालय दक्षिण-पूर्व रेलवे के उप-महाप्रवन्धक के कार्यालय को मध्य प्रदेश स्थिति विलासपुर से हटा कर उड़ीसा में मुवने-श्वर ग्रथवा किसी ग्रम्य स्थान पर ले जाना बाहता है; बौर (ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

रेल मंत्री (थो के हन्मर्ग्या): (क) बिलासपुर में उप-महाप्रबन्षक का कोई कार्या-इन्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेयड़ा स्टेझन (पूर्वीतर रेलवे) के समीप समीप एक रेलयाड़ी के 15 माल डिब्बों का उलटना

7067. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिन'क 28 मार्च 1972 के नवभारत टाइस्स के ग्रनुसार तेयड़ा रेलवे स्टेशन के सभीप एक रेलगाड़ी के 15 डिब्बे उल्ट गए; ग्रीर

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण थे तथा :सके परिणाम स्वरूप रेल विभाग को कितनी हानि हुई ?

रेस मंत्री (थी के• हनुमम्तैया) : (क) यह दुर्घटना 25-3-72 को टेघरा स्टेशन पर हई।

(ख) यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। मनुमान है कि रेल सम्पत्ति को लगभग 42,500 रु॰ की शति हई।

Holding up of Trains by Railway Staff

7068 SHRI B.K. DASCHOWDHURY: SHRI V. MAYAVAN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the incidents of holding up of trains by the Railway staff; (b) if so, the outcome thereof; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) to (c). The information is being collected and the same will be laid on the table of the Sabha.

Harijan Localities left out in Rural Electrification Programme

7069. SHRIS MURUGANAN'THAM: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that in some areas Harijan localities in villages were left out in the rural electrification programme,

(b) if so, the number of complaints received;

(c) whether any investigation has been made into these complaints; and

(d) if so, the findings thereof and the action taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B.N. KUREEL): (a) to (d). As it was observed that some Harijan bastis adjacent to already electrified villages were not electrified because of unremunerative loads in these areas and constraint of financial resources of the State Electricity Boards the Government of India have introduced since December, 1971, a Special Scheme for electrification of such Harijan Bastis. According to this Scheme, loan assistance at concessional terms is being provided through the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Boards for electrification of such Harijan Bastis. The loan carries an interest of 4 per cent per annum and is to be repaid over a period of 15 years. The Corporation has so far sanctioned ten such schemes of Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashira, Mysore, Nadu, West Ponjab, Rajasthan, Tamil